श्री केशव राव पारधी (भंडारा) : सभापति महोदय, महाराष्ट्र राज्य के जिला भण्डारा में जवाहर नगर (सर्वत्रनगर) में डिफेन्स फैक्टरी स्थापित है । जवाहर नगर तक भंडारा रोड से एक रेल लाइन पहले से ही बिछाई हुई है, किन्तु इस लाइन पर अभी तक एक भी लोकल ट्रेन नहीं चलती है जिसके कारण डिफेन्स फैक्टरी के कर्मचारियों को बहुत अधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है । डिफेन्स फैक्टरी के कर्मचारियों की तथा भण्डारा जिले के निवासियों की काफी दिनों से लगातार मांग चली आ रही है कि भण्डारा रोड से जवाहर नगर डिफेन्स फैक्टरी तक एक लोकल ट्रेन चलाई जाए, जिससे कि प्रतिदिन आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो । इस सम्बन्ध में मैं पहले कई बार रेल मंत्री जी, एवं रेलवे विभाग को कई पत्र लिख चुका, किन्तु दुःख है कि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है । भूतपूर्व रेल मंत्री ने अपने पत्र में लिखा था कि भंडारा रोड से जवाहर नगर के लिए बस सेवा चालू है, जिसके द्वारा समस्त कर्मचारी उससे आ-जा सकते हैं । यहां की जनता बहुत ही गरीब एवं पिछड़े वर्ग की है। बस का किराया अधिक होने के कारण, यहां की गरीब जनता उस किराये का बोझ उठाने के लिए असमर्थ है, यदि एक लोकल ट्रेन आरम्भ कर दी जाती है तो यहां की जनता को कम किराये में काम चल सकता है । भंडारा शहर की आबादी एक लाख से भी अधिक है, जिसका फायदा यहां के निवासियों को भी मिलेगा ।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह भंडारा रोड से जवाहर नगर डिफेन्स फैक्टरी तक एक लोकल ट्रेन चलाने के लिए अविलम्ब आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें जिससे कि यहां की जनता को राहत मिल सके।

(vii) NEWS COVERAGE ON NATIONAL ISSUES BY ALL INDIA RADIO

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) सभापति महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रीय मसलों पर आकाशवाणी का रवैया सही नहीं है ।

देश में अनमत कायम करने में आकाशवाणी का सब से बड़ा हाथ है । लेकिन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण के प्रश्न पर आकाशवाणी का जो रवैया रहा है, उसे निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता । यदि आप आकाशवाणी के समाचार बुलिटनों को देखें, तो जब से गुजरात में आरक्षण-विरोधी आन्दोलन शुरू हुआ, तब से आकाशवाणी ने आरक्षण के समर्थन में दिए गये वक्तव्यों को कम, लेकिन आरक्षण-विरोधी वक्तव्यों को अधिक उजागर किया है । दिनांक 30-3-81 रात्रि में कुछ संविधान निर्माताओं का नाम ले कर आरक्षण के विरोध में जो नहीं प्रसारण करना चाहिए, वह भी प्रसारित कर दिया गया । यहां तक कह डाला गया कि इन लोगों ने मांग की है कि न सिर्फ सरकारी नौकरियों में, बल्कि विधायिका क्षेत्रों में भी आरक्षण को तुरन्त खत्म कर देना चाहिए । लेकिन जब उस वक्तव्य की निन्दा करते हुए पांच संसद्-सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया, तो उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गई ।

इसके पहले भी सदन में गृह राज्य मंत्री द्वारा आन्दोलन में एक राजनीतिक पार्टी का हाथ होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इस पार्टी के एक दर्जन से अधिक संसद्-सदस्यों एवं नेताओं ने जब उसका प्रतिवाद किया और आरक्षण के पक्ष में वक्तव्य दिया, तो उसे प्रसारित नहीं किया गया ।

आरक्षण का सवाल इतना नाजुक है कि आकाशवाणी की थोड़ी सी भूल विस्फोट

[श्री राम विलास पासवान]

कर सकती है । राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा हो सकता है । संसद् ने एक स्वर से आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पास किया है । ऐसी स्थिति में आकाशवाणी द्वारा जान-बूझ कर ऐसा प्रसारण नहीं करना चाहिए, जिससे आन्दोलनकारियों एवं समाजविरोधी तत्वों को बल मिले । चूंकि आकाशवाणी सरकार के नियंत्रण में है, इस लिए सरकार पर भी दायित्व है कि वह ऐसे प्रसारण पर नजर रखे ।

15.53 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS 1981-82— *Contd.*

MINISRTY OF FETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS—*Contd.*

सभापति महोदय : अब सदन मिनिस्ट्री आफ़ पेट्रोलियम, केमिकल्ज एंड फर्टलाइजर्स की मांगों पर डिसकशन को जारी रखेगा ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (उदयपुर): सभापति महोदय, मैं मिनिस्ट्री आफ़ पेट्रोलियम, केमिकल्ज एंड फर्टलाइजर्ज की डिमाड्ज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमारे देश ने स्वावलम्बन प्राप्त करने की जो नीति निर्धारित की है, उसके अन्तर्गत जहां तक कृषि का सवाल है, ख़ास तौर से खाद्यान्नों का, दुनिया के कई मुल्क इस काम को नहीं कर पाए हैं, लेकिन भारत ने पिछले 32-33 वर्षों में स्वावलम्बन के लक्ष्य पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की है । आज जिस प्रकार से किसी भी देश के स्वावलम्बन के लिए खाद्यान्न अत्यन्त आवश्यक हैं, उसी प्रकार दुनिया की आज की परिस्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्राडक्ट्स भी उतना ही महत्व रखने वाले पदार्थ हैं । आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो स्थिति है, विशेष तौर से पिछले दो वर्ष से जो संघर्षमय स्थिति बनती चली जा रही है, उसमें किसी भी देश का—और भारत जैसे विशाल देश का—सारा आर्थिक ढांचा उथल-पुथल हो सकता है, अगर उसे बाहर से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्राडक्ट्स समय पर न मिले ।

ईराक और इरान की लड़ाई की वजह से हम लोगों को जबर्दस्त आघात लगा । हम बराबर पिछले दो वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कीमतों के बढ़ने की वजह से हम जो भी योजना तैयार करें या जो भी बजट प्रस्तुत करें, इनफ्लेशन पर जा कर तेल का क्या होगा, क्या नहीं, वह हमारे हाथ में नहीं रहा है । आज इम्पोर्टिड इनफ्लेशन ख़ास तौर से आयल प्राइसिज हमारी सारी आर्थिक स्थिति को इधर से उधर करने में बहुत बड़ा हाथ बंटा रही हैं । इस बात की सख्त आवश्यकता है कि हम जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनें और यह खुशी की बात है कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत काम करने वाले अलग अलग विभागों ने पिछले वर्षों के अन्दर जो कुछ खोज की और प्रयत्न किए उससे यह बात आउट आफ रीच नहीं मालूम होती बल्कि ऐसा मालूम होता है कि आने वाले पांच सात वर्षों के अन्दर अगर पूरे तौर से इस को लिया जाय और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस के लिए आवश्यक धन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध किया जायगा, उस हालत के अन्दर यह आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है । उस को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी रख कर नहीं चलना चाहिए